शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार
मध्यप्रदेश

इम्तिहान है...

माशिमं को परीक्षा कार्यक्रम में करना पड़ा बदलाव

कोरोना से अध्यापन प्रभावित अप्रैल अंत से होंगी परीक्षाएं

30 अप्रैल से प्रारंभ कराई जाएंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में कोरोना के प्रकोप से बच्चों की पढ़ाई का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल को कई सालों से चले आ रहे परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के शेड्यूल के अनुसार मार्च से ही 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ करवा दी जाती थी। इस बार भी अधिकारियों ने पूरे प्रयास किए कि मार्च से ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएं। लेकिन कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों कि जो रिपोर्ट सामने आई उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल को अपना निर्णय बदलना पड़ा है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि कोरोना संकटकाल में ऑनलाइन अध्यापन भी करवाया गया लेकिन बच्चे परीक्षाओं के लायक तैयार नहीं हुए। इस कारण परीक्षा का समय एक माह अतिरिक्त बढ़ाना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि जो परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं उसमें कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन करना जरूरी है।

एक माह आगे बढ़ाई परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि 30 अप्रैल से यह परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। 15 मई तक परीक्षाओं का समापन होगा। मंडल का कहना है कि अब परीक्षाएं विलंब से हो रही है तो फिर मूल्यांकन भी जुलाई अंत तक ही कम्प्लीट करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर मई तक परीक्षाएं समाप्त होंगी तो जून में पूरा मूल्यांकन होना संभव नहीं है। इस कारण परीक्षा का परिणाम भी देर से घोषित हो पाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाओं की तिथियां शीघ्र घोषित होंगी, इसके लिए तैयारी चल रही है।

परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर फोकस

अप्रैल में परीक्षाएं कराने का निर्णय कर चुका माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा ध्यान केंद्रों के निर्धारण पर टिक गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र में इस बार कई बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। नकल रोकने की तो पहले चुनौती है ही। दूसरा सबसे बड़ा संकट परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना भी है। इस कारण पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि मंडल की गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चे परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होंगे। गाइडलाइन का पालन कराने की जवाबदारी जिला कलेक्टरों की होगी। परीक्षाएं अपने स्तर पर कराने के लिए कलेक्टर पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।

इनका कहना है...

30 अप्रैल से परीक्षाएं कराना निश्चित किया गया है। कोरोना को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। जल्द ही परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जाएगा।

[illegible] सिंह, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारी चिंतित

रिवीजन टेस्ट में कमजोर आए बच्चों की अलग से कराना होगी तैयारी

भोपाल। पिछले महीने संपन्न करवाए गए रिवीजन टेस्ट में जो बच्चे कमजोर सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। कारण है कि अप्रैल में दसवीं बारहवीं की परीक्षाएं प्रस्तावित हो चुकी है और अभी बच्चों को विषय वार तैयारी की बड़ी जरूरत है। नवंबर माह के अंत में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों का रिवीजन टेस्ट करवाया गया था। यह एक प्रकार की अर्धवार्षिक परीक्षा थी। क्योंकि विभाग ने गाइडलाइन भी बनाई थी कि इस परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षाओं में जोड़े जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि रिवीजन टेस्ट में बड़ी संख्या में बच्चे कमजोर निकल कर सामने आए हैं। अकेले भोपाल में ही प्रत्येक स्कूल में ऐसे बच्चों की संख्या 100 से लेकर 200 तक है। भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्राचार्य द्वारा अपलोड किया गया था। अब उनसे परीक्षण करवाया जा रहा है कि कितने बच्चे इस परीक्षा में कम अंक लेकर सामने आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि ऐसे बच्चों की कक्षाओं में अलग से तैयारी करवाई जाएगी। इसको लेकर भी प्राचार्य को निर्देशित कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई कि वह स्वयं नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

विद्यार्थी में सौ प्रतिशत रिजल्ट का रखा गया है लक्ष्य: जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने भोपाल में समस्त संकुल प्राचार्य को निर्देशित भी कर दिया है कि इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का परिणाम सौ प्रतिशत लाना उनकी जवाबदारी होगी। इस कारण वे अभी से हर बच्चे पर नजर रखना शुरू कर दें। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य से साफ कहा है कि जिस विषय में बच्चे कमजोर सामने आएंगे। उस विषय के शिक्षक का पूरा रिपोर्ट विभाग को भेजा जाएगा। क्योंकि राज्य मुख्यालय से ही इस प्रकार के सख्त निर्देश हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन नितिन सक्सेना ने कहा है कि बच्चों की परीक्षा से पहले से तैयारी करवाने के लिए नियमित रूप से प्राचार्यों की बैठक ली जाएगी।

मुख्यमंत्री करेंगे बेटियों को सम्मानित

प्रदेश के [illegible] स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10वीं और 12वीं की बेटियों को सम्मानित करेंगे। महिला बाल विकास द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 11 जनवरी को यहां पर बेटियों को सम्मानित करेंगे। महिला बाल विकास के अधिकारियों का कहना है कि 11 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 10वीं एवं 12वीं की 11-11 बेटियों का सम्मान किया जाएगा।

बाल तस्करी का बड़ा कारण है भिक्षावृत्ति, सही रिपोर्टिंग नहीं

वेबिनार में विशेषज्ञों ने शेयर किए अनुभव

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9827229158

मानव तस्करी और खासकर बाल तस्करी की रिपोर्टिंग बेहद कम होती है। असल में गरीबी से जूझते समाज के बड़े वर्ग को बरगला कर उनके बच्चों को कथित सहमति से तस्करी में उपयोग किया जाता है। बिहार, बंगाल, छग, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे मामले अधिक है।

यह बात मानव संसाधन मंत्रालय के रिसर्च फैलो धनंजय बिंगल ने कही। वे बाल तस्करी पर आधारित चाइल्ड कंजर्वेशन के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृपाशंकर चौबे ने किया। आईपीएस जीके पाठक ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या रेस्क्यू किए गए बच्चों की पारिवारिक पहचान सुनिश्चित करना होती है। उन्होंने ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर एसपी के रूप में पोस्टिंग के दौरान के अनुभव और केसेस भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में ऐसे 700 बच्चों को परिवार में लौटाया, जो एक बड़ी चुनौती थी। अन्य वक्ताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी मैदानी स्तर पर बाल तस्करी रोकने सुव्यवस्थित तंत्र नहीं बन पाया है। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति का बाल तस्करी से गहरा संबंध है।

पुराने शहर के तीन प्रमुख सरकारी स्कूल भवनों की हालत खराब

जर्जर दीवारों, छत से उखड़ते प्लास्टर के बीच पढ़ाई की मजबूरी... मगर जिम्मेदार बेफिक्र

रामचंद्र पांडेय ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

जर्जर दीवारें, छत से गिरता प्लास्टर और लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण जर्जर हो चुकीं इमारतें...। यह तस्वीर राजधानी के उन तमाम सरकारी स्कूलों की है, जिनमें बच्चों की जान जोखिम में डालकर बाकायदा क्लास लगाई जाती हैं।

पीपुल्स समाचार
ग्राउंड रिपोर्ट

इनमें से एक इमारत की हालत तो इतनी खराब है, जिसका एक कमरा लॉक डाउन के दौरान ढह गया था। गनीमत यह रही थी कि उस दौरान स्कूल बंद थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पीपुल्स संवाददाता ने शुक्रवार को शहर के तीन बड़े स्कूलों का जायजा लिया, तो यह स्थिति सामने आई। इनमें जहांगीरिया स्कूल, हमीदिया स्कूल क्रमांक- 2 और कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। हालांकि कोरोना काल के कारण अभी तक रेगुलर क्लास शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

इस कमरे में लगती है क्लास

बारिश में हॉल गिर गया था, तब स्कूल बंद था वरना बड़ा हादसा हो जाता

1 पुराना शहर स्थित जहांगीरिया स्कूल लगभग 173 वर्ष पुराने भवन में लग रहा है। इस भवन का हॉल बारिश में ढह गया था। उस दौरान लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग जर्जर है। पहली से 12वीं तक यहां 166 विद्यार्थी हैं। इसका रखरखाव राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के माध्यम से होना है। इस्टीमेट बन गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

इस स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जैसी हस्तियां पढ़ चुकी हैं। अब भवन जर्जर होने से लोग अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराते हैं।

उषा खरे, प्राचार्य, शा.उ.मा. विद्यालय, जहांगीरिया, मोती मस्जिद

पीएससी की मुख्य परीक्षा 20 मार्च से ग्वालियर भी होगा केंद्र

इंदौर (नप्र)। मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मेंस के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। मुख्य परीक्षा 20 मार्च से होगी। पहली बार रतलाम, सतना, शहडोल और छिंदवाड़ा में भी मुख्य परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2019 नवंबर 2011 में घोषित हुई थी। आरक्षण विवाद के चलते प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में खासी देरी हुई। रिजल्ट दिसंबर 2020 में जारी किया गया। अब पीएससी ने घोषणा की है कि 11 जनवरी से नौ फरवरी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन वे ही उम्मीदवार जमा कर सकेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। 21 मार्च से 26 मार्च तक मुख्य परीक्षा होगी। इसके लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, शहडोल, छिंदवाड़ा और सतना में केंद्र होंगे। इससे पहले तक पीएससी संभागीय मुख्यालयों पर ही परीक्षा के केंद्र बनाता था। 10 मार्च से 21 मार्च तक प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

जेयू में फर्जी मार्कशीट के दोषियों पर कार्रवाई करने छह घंटे हंगामा

कुलपति निवास के बाहर धरना देते एबीवीपी के कार्यकर्ता। ● नईदुनिया

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नर्सिंग फर्जी मार्कशीट कांड के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जीवाजी विश्वविद्यालय में छह घंटे हंगामा किया।

कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस पर कुलसचिव आनंद मिश्रा उनकी मांगें सुनने आए। जब कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग फर्जी मार्कशीट कांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की तो उन्होंने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बता दिया। उन्होंने कहा इस मामले में कुलपति कार्रवाई कर सकती हैं। इसके बाद कार्यकर्ता दोपहर तीन बजे कुलपति बंगले पर पहुंचे और गेट के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। इस मामले में कुलपति संगीता शुक्ला का कहना है कि सात तारीख को मुझे समिति की रिपोर्ट मिली है। नर्सिंग कांड में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

इन मांगों को उठाया

नर्सिंग की निरस्त की गई मार्कशीटों व जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बीएससी तृतीय वर्ष भौतकी के प्रथम प्रश्न पत्र की कापियों का गलत मूल्यांकन किया गया है। इनका मूल्यांकन दोबारा किया जाए। जनरल प्रमोशन किए विद्यार्थियों से परीक्षा फीस किस आधार पर ली गई, जबकि परीक्षा का खर्च न के बराबर हुआ। यह फीस को लौटाई जाए आदि मांगों को उठाया गया है।

जेयू में बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष (परीक्षा जून 2019) के उन विद्यार्थियों को पास की मार्कशीटें जारी की गईं, जो फेल थे। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने अलग-अलग चार्ट बनाए गए थे। कार्य परिषद सदस्य अनूप अग्रवाल की शिकायत पर यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। जेयू ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जो रिपोर्ट जेयू को सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को उजागर नहीं की गई।

नपा सीट का 26 साल में नहीं बदला आरक्षण, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

ग्वालियर (नप्र)। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट के आरक्षण को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शासन को 15 जनवरी तक जवाब देने का आदेश दिया है। बलवीर मिश्रा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने तर्क दिया कि इंदरगंढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट को अनुसूचित जाति के लिए 1994 में आरक्षित किया गया था। इसे आरक्षित किए हुए 26 साल बीत गए हैं, लेकिन शासन ने इसके आरक्षण में बदलाव नहीं किया है। नियमानुसार हर पांच साल में आरक्षण बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस नियम का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने सुनवाई को बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर दिया।

'नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी, नहीं दे सकते दखल'

जबलपुर ।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 53 पदों के मुकाबले आधे ही पद भरे होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का इस टिप्पणी के साथ पटाक्षेप कर दिया गया कि नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, इसलिए फिलहाल दखल नहीं दे सकते। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विचार-मंथन जारी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डॉ.एमए खान व अमरजीत सिंह पनवार की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव व अभिमन्यु सिंह ने दलील दी कि मप्र हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 53 हैं, जबकि नियुक्त जज 28 ही हैं। -नईदुनिया प्रतिनिधि

अदालत जाने के पक्ष में नहीं हैं।

और जो नहीं चाहते वे नहीं करें।

किया है।

एंकर स्टोरी

लॉकडाउन से पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के साथ-साथ आम जनता का दिल जीतने का प्रयास

कश्मीर में बच्चों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही सेना

श्रीनगर, जेएनएन। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस का इंतजाम किया है। सेना ने वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था की है। ये कक्षाएं उत्तरी कश्मीर के कम से कम एक दर्जन इलाकों में लगाई जा रही हैं। खास बात ये है कि इन कक्षाओं में सैनिक स्वयं भी पढ़ाने के लिए जाते हैं। हालांकि, राज्य के प्राइमरी शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाई है। हर कोचिंग में पांच-पांच अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जब किसी कारण से अध्यापक अनुपस्थित हो जाता है, तो सर्दी वर्दी में सैनिक स्वयं भी मोर्चा संभालते हैं। इतना ही नहीं, सेना के अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं।

ट्यूशन केंद्रों की निगरानी के लिए बारामुला में एक सेंटर भी स्थापित किया गया है। इस सेंटर से ही तय होता है कि किस ट्यूशन केंद्र पर कौन पढ़ाने जाएगा। इन केंद्रों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और डोगरी सहित कुछ विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं। इनके अलावा सभी विषय इन केंद्रों पर पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चों को परीक्षा के समय कोई परेशानी न हो, साथ ही उनका देश और विदेश के बारे में ज्ञान भी बढ़े। इससे सेना आम कश्मीरियों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। जब सैनिक बच्चों का दिल जीत लेते हैं, तो उनके माता-पिता का सैनिकों पर भरोसा बढ़ जाता है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को देखते हुए इसी नुकसान की भरपाई के लिए सेना ने यह जिम्मा उठाया है। इस ट्यूशन क्लासेस के दौरान हर 15 दिन में बच्चों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्टेशनरी आइटम भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इस दौरान कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो सेना उसका अपनी निगरानी में उपचार कराती है।

हर क्लास में 50-50 बच्चे

इन सभी ट्यूशन क्लास में 50-50 बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनमें 30 लड़के और 20 लड़कियां शामिल की गई हैं। एक क्लास में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट नेलोफर राशिद ने बताया कि हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें फ्री में पढ़ाने के बारे में सोचा। सेना की ओर से लगाई जा रही ट्यूशन क्लासेस में 5 लोकल टीचर्स को बुलाया जा रहा है। यहां पढ़ाने आ रहे एक टीचर हिलाल अहमद ने बताया कि मैं यहां उर्दू पढ़ाता हूं। बच्चों को फ्री पढ़ाने से हमारे लिए भी रोजगार के रास्ते खुले हैं।

मजबूत हो रहा अवाम और जवान का रिश्ता

सेना की इस पहल से अवाम और जवान का रिश्ता मजबूत हो रहा है। ट्यूशन क्लास में बच्चों को फ्री में पढ़ाने और उन्हें सभी सुविधाएं देने के पीछे एक मकसद भी यही है कि राज्य की जनता से सेना का रिश्ता सुधरे। बता दें कि सेना इस तरह के प्रयास हमेशा करती रहती है, जिससे अवाम और जवान का रिश्ता सुधरे। हाल ही में शोपोर में बर्फबारी में फंसी एक गर्भवती महिला को सेना के जवान पालकी में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। जब भी घाटी में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सेना के जवान जनता की ढाल बन जाते हैं। इसका सकारात्मक असर भी पड़ रहा है। हालांकि, कुछ इलाकों में अब भी सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं। कहीं-कहीं स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगते हैं।

छठवीं से आठवीं तक के डेढ़ लाख विद्यार्थी नए सत्र से डेस्क-बेंच पर बैठ करेंगे पढ़ाई

स्टार समाचार | भोपाल

नए सत्र में छठवीं से आठवीं तक के सरकारी स्कूल खुलेंगे तो इनके विद्यार्थी डेस्क-बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माध्यमिक स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एक परिसर एक शाला के स्कूलों में छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। इसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला मिशन संचालकों को दिए निर्देश दे दिए हैं। निर्देश में यह भी लिखा है कि फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए जिले के एक परिसर एक शाला में से स्कूलों का चयन कर

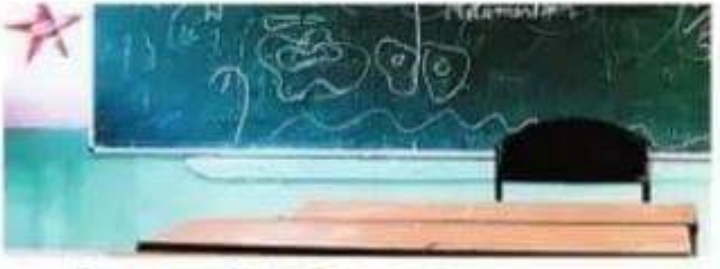

इन जिलों के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा

इसमें शिवपुरी व धार के 5050, सागर के 5200, छिंदवाड़ा के 4950, खरगोन के 4200, सतना के 4550, बैतूल के 4050 विद्यार्थियों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। यू-डाइस 2019-20 के अनुसार कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।

पीएससी पर कोरोना का असर, 4 की जगह 8 शहरों में होगी मुख्य परीक्षा

भोपाल। मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने राज्य सेवा (मेन्स) परीक्षा 2019 की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 27 से 26 मार्च के बीच कराई जाएगी। पहली बार इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा चार और शहर शामिल किए गए हैं। इस बार छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना और शहडोल में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के जरिए अलग-अलग विभाग के 571 पदों पर भर्ती की जाना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा जनवरी 2020 में कराई गई थी, जिसके नतीजे हाल ही में जारी किए गए हैं। अब करीब सवा साल बाद मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। वर्तमान में कोरोना को देखते हुए इस परीक्षा के लिए पीएससी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की मानी गई। इससे निपटने के लिए इस बार चार की जगह आठ शहरों में परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। पीएससी में चयनित उम्मीदवारों से 11 जनवरी से 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 16 फरवरी तक 3 हजार रुपए और 17 फरवरी से 13 मार्च तक 25 हजार रुपए लेट फीस के साथ आवेदन होंगे।

मप्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार, 17 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी

स्टार समाचार | भोपाल

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को फिलहाल 14 फीसदी आरक्षण ही मिल सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक बरकरार रखी है। इस मामले पर अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

एक घंटे तक चली बहस

ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम बहस की सुनवाई तय कर दी है। करीब 1 घण्टे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तय किया है कि 4 हफ्ते बाद अब मामले पर फाइनल हियरिंग यानि अंतिम बहस सुनी जाएगी।

50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं

कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। सरकार के उस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में साफ किया था कि ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग सबको मिलाकर कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने से आरक्षण का दायरा 63 प्रतिशत पहुंच गया है। इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए बढ़ा हुआ 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। इसे हाईकोर्ट ने जारी रखा है।

इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं

■ 11 से 15 जनवरी तक होंगे प्रेक्टिकल

स्टार समाचार | रीवा

शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा आनलाइन होगी। कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में कॉलेजों की कक्षाएं नहीं संचालित हो रही हैं। वहीं तकनीकी शिक्षण विभाग ने कॉलेजों को शुरू करने के संबंध में अब तक कोई आदेश भी जारी नहीं किया है जबकि बाकी गैर तकनीकी कॉलेज शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन करानी होगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच प्रेक्टिकल परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्देश दिया था जिसका पालन करते हुए कॉलेज प्रबंधन ने 11 से 15 जनवरी तक प्रेक्टिकल परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि प्रेक्टिकल परीक्षा तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर की होगी।

ऑनलाइन प्रेक्टिकल परीक्षा एक प्रयोग

कोरोना महामारी ने कॉलेजों का अध्ययन-अध्यापन पूरा डिजिटल कर दिया है। मगर प्रेक्टिकल जैसी परीक्षा जो बिना उपस्थित हुए बिना असंभव मानी जाती थी, कोरोना ने उसे भी संभव कर दिया। यह सुनने में ही अटपटा लगता है कि प्रेक्टिकल ऑनलाइन होंगे। तकनीकी शिक्षण ने ऑनलाइन प्रेक्टिकल परीक्षा आयोजित कराने का एक प्रयोग किया है। देखना यह है कि यह कितना सफल होता है।

प्रायोगिक के नाम पर होगा सिर्फ वाइवा

बताया गया है कि परीक्षाओं के लिए परीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। एक तरफ से छात्र अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप पर रहेगा और दूसरी तरफ कम्प्यूटर पर शिक्षक होंगे। यहां से शिक्षक छात्रों से सवाल पूछेंगे और छात्रों द्वारा तैयार किए गए प्रेक्टिकल से जुड़े उत्तर देने होंगे। गौरतलब है कि कोरोना के कारण ऑफ लाइन कक्षाएं लगी ही नहीं और न ही भौतिक रूप से प्रेक्टिकल हुए। यही वजह है कि प्रायोगिक परीक्षा में सिर्फ वाइवा होगा।

परीक्षा देरी से और रिजल्ट समय पर जारी करने माशिमं कर रहा व्यवस्था

इस बार जिले में ही जांची जाएंगी बोर्ड की कॉपियां

स्टार समाचार | रीवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षा में कई बदलाव कर दिए हैं। सेलेबस घटाना, ऑनलाइन प्री-बोर्ड परीक्षा होना, दो माह देरी से बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने के साथ कॉपियां भी जिले में ही जांचने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा का तात्पर्य ही यही है कि कॉपियों को अलग-अलग जिलों में दूसरे शिक्षकों से जंचवाई जाए। परंतु कोरोना महामारी ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि सारे नियम कायदे ही बदलने पड़ गए।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भले ही दो माह देरी से परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है मगर परिणाम जल्दी जारी करने की भी योजना बना रहा है। यही वजह है कि इस बार कॉपियों को जिले में ही जांचने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि जैसे ही किसी विषय का पेपर समाप्त होगा, उसके अगले दिन से कॉपी जांचने का काम प्रारंभ हो जाएगा। एक-एक विषय का रिजल्ट समन्वयक केन्द्रों से बोर्ड को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। जिससे विषयवार रिजल्ट माशिमं की वेबसाइट में प्रदर्शित होने लगेंगे।

हर विषय का करवा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन

इस बार विषयवार कॉपियों का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होता रहेगा। बोर्ड परीक्षा में कम नंबर पाने वाले छात्र उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन भी करा सकेंगे। गौरतलब है कि अब तक सिर्फ पुनर्गणना का विकल्प दिया जाता था मगर इस बार पुनर्मूल्यांकन की भी व्यवस्था कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों को बोर्ड से मिले अंकों पर संदेह हो वह हर विषय का पुनर्मूल्यांकन करा सकेंगे।

30 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगी परीक्षाएं

बताया गया है कि दसवीं व बारहवीं की पहली परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 मई तक चलेगी। वहीं दूसरी परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगी। बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था कर दी है। पहले आठ दिन कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराने पर सौ रुपए उसके आठ दिन बाद 50 रुपए और उसके भी बाद पुनर्मूल्यांकन कराने पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ऐसा यह पहला मौका है जब बोर्ड की परीक्षा देरी से आयोजित तो हो ही रही है साथ ही दो बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित हो रही है।

40 किमी के दायरे में आने वाले शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी

बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षकों को 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। इससे पहले यह दूरी 80 किलोमीटर तक थी। जिस शिक्षक को भी जो केन्द्र मिल जाता था उसे रोजाना केन्द्र पहुंचना पड़ता था। बताया गया है कि ज्यादा दूरी होने के कारण शिक्षक सड़क हादसे का शिकार हो जाती थी। ऐसी ही घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए 80 से दूरी 40 किलोमीटर कर दी गई है।

वॉट्सऐप ने बदली प्राइवेसी पॉलिसी, आपकी चैट, कॉल नहीं रहेगी पर्सनल!

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होगी। इन्हें स्वीकार नहीं करने पर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसे में यूजर्स को अपना डाटा शेयर होने का खतरा सताने लगा है। इसे लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लंबी बहस हुई। एक यूजर ने लिखा- काफी लोगों को अब वाट्सअप छोड़ना होगा। नई पॉलिसी स्वीकार करते ही आपकी कॉल, जानकारियां सब इस्तेमाल हो सकती हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- यानी, अब वॉट्सएप कॉल और मैसेज दो लोगों के बीच की बात नहीं रहेंगे। इस बीच दुनिया के नंबर वन अमीर ***एलन मस्क*** ने बताया कि वह वाट्सएप का प्रयोग नहीं करते बल्कि 'सिग्नल' यूज करते हैं। उन्होंने लिखा - 'यूज सिग्नल।' उनके ट्वीट के बाद सिग्नल के 10 करोड़ डाउनलोड हो गए।

मस्क ने कहा- सिग्नल ऐप यूज करें

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पहले और अब...

पहले : आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जबसे वॉट्सऐप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें।

अब : हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डाटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं।

यानी... वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और अन्य कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है।

एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा मार्च में

इंदौर। मप्र लोकसेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मेंस परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। मुख्य परीक्षा 21 से 26 मार्च तक होगी। इंदौर के साथ ही सतना, रतलाम, शहडोल और छिंदवाड़ा में भी मुख्य परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे। इस बार भी पेन और पेपर पर ही परीक्षा ली जाएगी।

वॉट्सऐप ने बदली प्राइवेसी पॉलिसी, आपकी चैट, कॉल नहीं रहेगी पर्सनल!

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होगी। इन्हें स्वीकार नहीं करने पर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसे में यूजर्स को अपना डाटा शेयर होने का खतरा सताने लगा है। इसे लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लंबी बहस हुई। एक यूजर ने लिखा- काफी लोगों को अब वाट्सअप छोड़ना होगा। नई पॉलिसी स्वीकार करते ही आपकी कॉल, जानकारियां सब इस्तेमाल हो सकती हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- यानी, अब वॉट्सएप कॉल और मैसेज दो लोगों के बीच की बात नहीं रहेंगे। इस बीच दुनिया के नंबर वन अमीर ***एलन मस्क*** ने बताया कि वह वाट्सएप का प्रयोग नहीं करते बल्कि 'सिग्नल' यूज करते हैं। उन्होंने लिखा - 'यूज सिग्नल।' उनके ट्वीट के बाद सिग्नल के 10 करोड़ डाउनलोड हो गए।

मस्क ने कहा- सिग्नल ऐप यूज करें

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पहले और अब...

पहले : आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जबसे वॉट्सऐप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें।

अब : हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डाटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं।

यानी... वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और अन्य कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है।

BU:फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होने से UG-PG के स्टूडेंट्स परेशान

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के यूजी-पीजी के 10 हजार से अधिक उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होने के चलते एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं दूरदराज के स्टूडेंट भी रिजल्ट जानने के लिए विवि के चक्कर लगा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि उन्होंने ओपेन बुक सिस्टम से एग्जाम दिया,असाइनमेंट भी जमा किए। बावजूद इसके विवि ने रिजल्ट अटका रखा है। सीएम हेल्पलाइन में आ रहीं लगातार शिकायतों को लेकर बीयू कुलपति प्रो. आरजे राव ने गुरूवार को बैठक भी बुलाई थी।

ऐसे जारी होना था रिजल्ट

उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट पहले और दूसरे सेमेस्टर के 50 प्रतिशत अंक और तीसरे और चौथे सेमेस्टर के 50 फीसदी अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी होना था,लेकिन इसके पहले किसी स्टूडेंट का ऐटीकेटी है तो उसका रिजल्ट जीरो बनाया गया है। इसके चलते स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं।

जीएमसी में डॉक्टर, स्टाफ नर्स आदि के लिए इंटरव्यू 9 को होंगे

भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन, स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर **नियुक्ति** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए बीते साल सितंबर में आवेदन बुलाए गए थे, लेकिन कोरोना के चलते इंटरव्यू टाल दिए गए थे। अब जीएमसी प्रबंधन ने 9 जनवरी को साक्षात्कार आयोजित किया है। इन पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर की जा रही है। स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी, एनेस्थिसिया विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक सर्जन, फिजियोथैरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और सोशल वर्कर आदि के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे।

प्रतिनियुक्ति पाने अब नहीं चलेगा PHQ में सादा आवेदन

प्रसं, भोपाल। केंद्र के साथ ही अन्य राज्यों और प्रदेश के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने की चाह रखने वालों पुलिस आरक्षक से लेकर निरीक्षकों स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब पुलिस मुख्यालय में केवल आवेदन देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अब नई व्यवस्था पुलिस मुख्यालय ने लागू कर दी है। नये साल में अब इस व्यवस्था के तहत आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अफसर-कर्मचारियों को आवेदन निधारित प्रारूप में करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इनके इकाई प्रमुख को सजा और आपराधिक प्रकरण की जानकारी देते हुए टीप लगाना होगी। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने पुलिस की सभी इकाईयों को इस संबंध में निदेश जारी किए गए हैं। जिसमें बताया गया है कि अब आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अफसर-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए सादा आवेदन नहीं करेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप के ही आवेदन किए जाएंगे। साथ ही प्रारूप में किए गए आवेदन पर ही अनुशंसा की जाए। बिना प्रारूप के आवेदन मान्य नहीं किए जाएं। प्रारूप में भरे आवेदन पर ईकाई प्रमुख अपनी टीप लगाकर पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे।

गढ़ाकोटा की घटना• ब्रेकर पर पहिया आते ही उछला ऑटो तो नीचे गिर गई थी छात्रा, ऑटो चालक के खिलाफ दर्ज हुआ केस

10वीं की टॉपर रही छात्रा तेज रफ्तार ऑटो से गिरी, मौत

भास्कर संवाददाता | सागर/ गढ़ाकोटा

छात्रा अनुपमा

गढ़ाकोटा के बसारी गांव के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ऑटो से गिरने से कक्षा 11 वीं की होनहार छात्रा की मौत हो गई। वह 10 कक्षा में 90 प्रतिशत अंक लेकर पास होने के साथ ही गढ़ाकोटा की टॉपर रही है। ओवरलोड ऑटो में स्कूल के और भी विद्यार्थी बैठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से जार रहे ऑटो का पहिया जैसे ही ब्रेकर पर पड़ा तो छात्रा के हाथ की पकड़ छूट गई और वह नीचे गिर गई। छात्रा के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक गढ़ाकोटा से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रपुरा गांव से शुक्रवार सुबह ऑटो क्रमांक एमपी 34 आर 2179 से छात्र-छात्राएं गढ़ाकोटा पढ़ने के लिए आ रहे थे। सुबह करीब साढ़े 10 बजे बसारी गांव के पास यह हादसा हुआ। लोगों के बताए अनुसार घटना के वक्त ऑटो में एक दर्जन से अधिक विद्यार्थी सवार थे। छात्रा अनुपमा विश्वकर्मा ऑटो में साइड की तरफ बैठी थी। ऑटो चालक की लापरवाही से वह नीचे गिर गई। छात्रा के सिर और कंधे में अंदरूनी चोटें आई। घटना के बाद ऑटो चालक ही छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंचा।

6 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी अनुपमा, सांस्कृतिक गतिविधियों में लेती थी भाग

गढ़ाकोटा की शासकीय कन्या हाई सेकेण्डरी स्कूल की प्राचार्य सरोज तिवारी ने बताया कि अनुपमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। 10 वीं कक्षा में उसने 90 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे गढ़ाकोटा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह नियमित स्कूल आती थी। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी वह बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थी। गांव में स्कूल मिडिल तक होने की वजह से गांव के बच्चे हाई स्कूल में आने के बाद गढ़ाकोटा पढ़ने के लिए आते हैं। अनुपमा के पिता दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि वह 6 भाई-बहिनों में सबसे छोटी थी और पढ़ने में सबसे अच्छी थी। अनुपमा से बड़ी तीन बहन व दो भाई हैं।गढ़ाकोटा टीआई प्रशांत मिश्रा ने बताया कि ऑटो चालक कमोदी अहिरवार के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

14 फीसद से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 फीसद से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है। - **नप्र**

गाइडलाइन ताक पर• कॉलेजों में प्रैक्टिकल के दौरान लापरवाही

टोकने के बावजूद नोट्स के बहाने बार बार ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

बार-बार बोलने के बाद भी पास-पास बैठ जाते हो, आखिर आपको कितनी बार कहना पड़ेगा..सभी आपस में डिस्टेंस मैंटेन करके रखिए.. क्लास में जब जगह खाली है तो दूर-दूर बैठने में क्या परेशानी है? आपको पता होना चाहिए कि यह समय कोरोना संक्रमण का है। इसलिए सावधानी रखनी होगी। यह समझाइश मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय (एमवीएम) में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से लगी प्रैक्टिकल क्लास के दौरान प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को दे रहीं थी। खास बात यह है कि इस क्लास में बीएससी सेकंड ईयर के 12 स्टूडेंट्स ही थे। लेकिन इन्हें भी दूर-दूर बैठने के लिए कहना पड़ा। प्रोफेसर्स बताते हैं कि वे छात्रों को दस बार दूर बैठने के लिए समझाना पड़ रहा है। लेकिन किताब देखने, नोट्स देखने के बहाने वे फिर से सटकर बैठ जाते हैं।

एमवीएम... हिदायत के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं स्टूडेंट

10 से लगेंगी थ्योरी क्लास....कॉलेजों में अब 10 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं लगना शुरू हो रही हैं। अब कैंपस में अधिक भीड़ होगी।

क्लास में पाबंदी, कैंपस में आजादी

कॉलेजों के कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच कोरोना के इस दौर का अधिक असर नहीं दिख रहा है। वे अपनी मौज में हैं। कैंपस में ग्रुप बनाकर खड़े हैं। हाथ पकड़कर चल रहे हैं। क्लासरूम के बाहर एक साथ बैठे हैं। यहां तक की क्लासरूम में भी दूर बैठाने के लिए बार-बार हिदायत देनी पड़ रही है।

एसओपी का पालन हो रहा है

कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी एसओपी का पालन किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट को थर्मल स्कैनर दिया है। सोशल डिस्टेंस का पालन हो इसके लिए छात्रों को बार-बार हिदायत दी जाती है। इसमें सख्ती भी की जाएगी।

डॉ. महेंद्र सिंह, प्रभारी प्राचार्य एमवीएम

जबलपुर : 14 फीसदी से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक जारी

जबलपुर | मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को जारी रखते हुए मामले की अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को नियत की है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके खिलाफ जबलपुर निवासी असिता दुबे और अन्य की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले फैसले में स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिए जाने से आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत को पार कर गई है।

बुरहानपुर : 0 साल बाद दिखा फॉरेस्ट

डीबी स्टार एक्सक्लूसिव आपके टैक्स के पैसों से बिचौली मर्दाना में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के स्कूलों के सामने लगाए पैवर

पूरा गांव छोड़ निगम अफसरों ने पूर्व विधायक पटेल के स्कूलों के बाहर खर्च किए 14 लाख

इंदौर • डीबी स्टार

शहर में विकास कार्यों के लिए फंड का रोना रोने वाले नगर निगम के अधिकारियों ने आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों में से 14 लाख रुपए खर्च कर वार्ड 78 के तहत बिचौली मर्दाना में दो निजी स्कूल- प्रज्ञा और विद्यासागर स्कूल के सामने पैवर ब्लॉक लगवा दिए। ये दोनों स्कूल पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के हैं। निगम अफसरों ने इन 'खास स्कूलों' पर तो इनायत कर दी, जबकि इसी वार्ड के रहवासी इलाकों में पैवर ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव तक नहीं बनाया है।

नगर निगम के नियमों में कहीं भी निजी स्कूल या किसी संस्था को फायदा पहुंचाने का जिक्र नहीं है, फिर भी अधिकारी जनता की गाढ़ी कमाई से स्कूलों के आगे सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। निगम के जोन क्रमांक 19 के अफसरों ने 14 लाख रुपए की लागत से प्रज्ञा और विद्यासागर स्कूलों के सामने पैवर ब्लॉक लगवा दिए हैं। इस जगह का इस्तेमाल स्कूलों में आने वाले वाहनों की पार्किंग के तौर पर किया जाता है, लेकिन निगम अधिकारियों ने बाकायदा प्रस्ताव बनाकर टेंडर के मार्फत यहां काम पूरा करा दिया है। बिचौली मर्दाना क्षेत्र में कई स्थानों पर पैवर ब्लॉक की दरकार होने के बावजूद वहां काम करने का प्रस्ताव तक नहीं बनाया गया है।

खास स्कूलों पर इनायत

आम रास्तों पर आफत

ये हैं जिम्मेदार जनता के पैसों के इस इस्तेमाल के लिए... अब जवाब देने से बच रहे हैं

वैभव देवलासे : जोनल अधिकारी, जो काम का प्रस्ताव बनाते हैं

अशोक राठौर : सिटी इंजीनियर, जो प्रस्ताव को देते हैं मंजूरी

निगम की सीमा में पैवर ब्लॉक लगाने या अन्य कोई भी काम कराने के लिए पार्षद या जनता की मांग पर संबंधित जोन के जोनल अधिकारी प्रस्ताव तैयार करते हैं। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए जनकार्य विभाग को भेजा जाता है। वहां के सिटी इंजीनियर इस प्रस्ताव पर अनुमति देते हैं। इसके बाद प्रस्ताव की फाइल वापस जोन कार्यालय पर आती है। इस फाइल के हिसाब से जेडओ टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर काम पूरा कराते हैं। इस तरह के तमाम कामों की निगरानी जेडओ और संबंधित सब इंजीनियर के अधीन होती है। जोन-19 के सब इंजीनियर अनिल शर्मा के मुताबिक, प्रज्ञा स्कूल के सामने पैवर लगाने का प्रस्ताव जेडओ वैभव देवलासे ने तैयार किया था। इस पर सिटी इंजीनियर अशोक राठौर की अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू किया गया था।

सत्यनारायण पटेल

इस मामले में डीबी स्टार ने देवलासे से तीन दिन तक बात करने का प्रयास किया। बात करने से बचने के लिए उन्होंने रिपोर्टर का नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया। सिटी इंजीनियर अशोक राठौर ने भी बात नहीं की। प्रज्ञा स्कूल और विद्यासागर स्कूल के मालिक कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल से भी उनका पक्ष जानने के लिए डीबी स्टार ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा।

जल्दबाजी इतनी : बायपास से गांव तक पैवर लगवाने का प्रस्ताव किया खारिज

इस मामले में डीबी स्टार द्वारा की गई पड़ताल में पता चला कि नगर निगम अधिकारियों ने पहले बायपास से बिचौली मर्दाना और वार्ड 76 की अन्य कॉलोनियों को जोड़ने वाले रास्ते के दोनों तरफ पैवर ब्लॉक लगाने की योजना बनाई थी। बाद में मौखिक तौर पर इस प्रस्ताव को खारिज कर सिर्फ प्रज्ञा और विद्यासागर स्कूल के सामने वाले हिस्से में दोनों तरफ पैवर ब्लॉक लगाने का आदेश दिया। इसी आदेश के आधार पर प्रस्ताव बना और 14 लाख रुपए खर्च कर कांग्रेस नेता पटेल के इन दो निजी स्कूलों के बाहर पैवर ब्लॉक लगवा दिए गए। इस काम की निगरानी कर रहे नगर निगम के जोन-19 के सब इंजीनियर अनिल शर्मा के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसा आदेश दिया, उन्होंने वैसा काम करवा दिया।

हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश दिया था इसके लिए

बिचौली मर्दाना में पहले बायपास से लेकर प्रज्ञा और विद्यासागर स्कूल तक पैवर लगाने का प्रस्ताव था। बाद में हमें कहा गया कि सिर्फ स्कूल के सामने वाले हिस्से में सड़क के दोनों तरफ पैवर लगाना है। हमने आदेश के मुताबिक यहां पैवर ब्लॉक लगवा दिए हैं। अधिकारियों ने यह आदेश क्यों दिए, इसका जवाब वे ही दे सकते हैं। **-अनिल शर्मा,**
सब इंजीनियर जोन-19 नगर निगम

बिचौली मर्दाना-देवगुराड़िया रोड का काम ढाई माह से बंद

बिचौली मर्दाना को देवगुराड़िया से जोड़ने वाली सड़क का काम करीब ढाई महीने से बंद है। रहवासी राहुल कुमार ने बताया कि करीब छह माह पहले निगम ने एक किमी लंबे इस मार्ग पर देवगुराड़िया वाले हिस्से से सड़क का काम शुरू किया था। बाकी हिस्सों में आधी सड़क की खुदाई की गई थी। करीब तीन माह काम चला और नोबल हॉस्पिटल तक सड़क भी बन गई, लेकिन दीपावली के कुछ दिन पहले से काम बंद कर दिया गया। खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई है। वहीं, निगम के मुख्य अभीक्षण यंत्री सुनील गुप्ता ने कहा कि इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे।

सीधी बात प्रतिभा पाल, आयुक्त नगर निगम

स्कूल को फायदा पहुंचाया है तो प्रबंधन से वसूली करेंगे

•बिचौली मर्दाना में प्रज्ञा और विद्यासागर स्कूल के सामने वाले हिस्से में निगम के खर्च पर पैवर ब्लॉक क्यों लगाए गए हैं?
- यदि वहां सरकारी जमीन है तो निगम के खर्च से पैवर लगाए गए होंगे।

•लेकिन वह जमीन दोनों स्कूल की पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है?
- तब तो यह जांच का विषय है।

•बिचौली मर्दाना में इसी सड़क के बाकी हिस्से में कहीं और क्यों पैवर नहीं लगाए गए?
- इस बारे में वहां के जोनल अधिकारी से समझना पड़ेगा।

•वहां और भी ऐसी कई सड़कें हैं, जहां लोगों की आवाजाही होती है। वहां नालियां खुली पड़ी हैं। लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है। वहां भी पैवर नहीं लगाए गए?
- हम उस जोन के अधिकारियों से बात करने के बाद जांच करेंगे। अगर निजी स्कूल को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है तो निगम के बजट से खर्च की गई राशि स्कूल प्रबंधन से वसूलेंगे।

आज का इतिहास

द. अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी

महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को 'भारतीय प्रवासी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी जी मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। 1915 में सरकार की ओर से उन्हें 'कैसर-ए-हिन्द' स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। एक प्रवासी वकील के रूप में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया था।

09 जनवरी की प्रमुख घटनाएं...

1768 - फिलिप एस्टले ने पहले 'मॉर्डन सर्कस' का प्रदर्शन किया।

1816 - सर हम्फ्री डेवी ने खदानकर्मियों के लिए पहले 'डेवी लैम्प' का परीक्षण किया।

1923 - जुआन डि ला सिएर्वा ने पहली 'ऑटोगायरो फ्लाइट' का निर्माण किया।

1941 - यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6 हजार यहूदियों की हत्या।

1970 - सिंगापुर में संविधान अपनाया गया।

1982 - पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था।

2008 - श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के इलाके पर कब्जा किया।

आज का इतिहास

- **1431:** फ्रांस में 'जोन ऑफ आर्क' के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई।
- **1718:** फ्रांस ने स्पेन के ख़िलाफ़ लड़ाई की घोषणा की।
- **1768:** फिलिप एस्टले ने पहले 'मॉर्डन सर्कस' का प्रदर्शन किया।
- **1792:** तुर्की और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- **1816:** सर हम्फ्री डेवी ने खदानकर्मियों के लिए पहल 'डेवी लैम्प' का परीक्षण किया।
- **1914:** महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।
- **1915:** महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद बम्बई (अब मुंबई) पहुंचे।
- **2007:** जापान में पहला राज्य मंत्रालय गठित हुआ।
- **2008:** श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के इलाके पर कब्ज़ा किया।

आज का इतिहास

1889 वृंदावनलाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार का जन्म हुआ।

1927 सुन्दरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेता का जन्म हुआ।

1934 महेन्द्र कपूर हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक का जन्म हुआ।

1914 महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।

1970 सिंगापुर में संविधान अपनाया गया।

1982 पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा।

2001 बांग्लादेश में हिन्दुओं की सम्पत्ति लौटाने संबंधी विधेयक मंजूर।